



ऑइल पाम बगानों के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को काटने की जब बात होती है तो इससे प्रभावित होने वाले जानवरों में सबसे पहले ओरंगुटान का नाम ज़हन में आता है। पर एक और जानवर है जिसे वर्षा वनों की कटाई का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी जितना सोचा गया था उससे बहुत ज्यादा। यह जीव है मार्बल कैट। एक नए शोध से पता चला है कि, पेड़ों पर रहने वाली यह बिल्ली इस कदर प्रभावित हुई है कि, इसका स्तर "निअर ग्रैंटंड" की बजाय "वल्नेरेबल" करने का सुझाव दिया गया है। जर्नल इकोस्फिअर में छपे इस शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि, जंगल साफ करने व पाम ऑयल बगानों के प्रति मार्बल कैट की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। शोध के प्रथम लेखक, युनिवर्सिटी ऑफ क्वीन्सलैंड के अलैक्जेंडर हैन्ड्री ने कहा, मार्बल कैट ने हमारी इस अवधारणा की पुष्टि की कि, जीवन का आधा समय पेड़ों पर बिताते वाले जानवरों (सैमी आरबोरिअल एनिमल्स) पर वर्षावनों के घटने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हैन्ड्री के अनुसार, कैमरा ट्रैप डेटा से इस बात की पुष्टि हुई है कि, यह बिल्ली जंगल की कर्नेक्टिविटी पर निर्भर है। तथापि, हैन्ड्री ने कहा कि, जमीन पर रहने वाली लैपड कैट की प्रतिक्रिया इससे एकदम उलट थी। शोध में पाया गया कि इन जानवरों ने ऑयल पाम बगानों के एनवायरनमेंट से अनुकूलन कर लिया। इससे स्पष्ट है कि, संभवतया मार्बल कैट, पेड़ों पर रहने की, अपनी "सैमी आरबोरिअल" प्रकृति के कारण वनों के विनाश से उत्पन्न स्थिति से अनुकूलन नहीं कर पा रही है। नतीजों से यह भी पता चला कि, मार्बल कैट इसानी गतिविधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर ये बिल्लियाँ दिन में एक्टिव रहती हैं पर कई बार इन्हें देर शाम को भी सक्रिय देखा गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दिन में इसानी गतिविधियाँ ज्यादा होती हैं। ऐसा लगता है कि, इसानी से दूर रहने के लिए वो ऐसा करती हैं। लेकिन यदि ऐसा ही होता रहा तो मार्बल कैट के पास शिकार के लिए कम समय रह जाएगा और हो सकता है उन्हें नए प्रतिद्वंद्वियों व परभक्षियों का सामना करना पड़े। इन नतीजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि, ऑइल पाम प्लांटेशन की वजह से मार्बल कैट को, पूर्व में जितना सोचा गया था, उससे ज्यादा खतरा है।

'राहुल गांधी दिल्ली में अडानी के भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलित हैं और मैं राजे के खिलाफ जयपुर में'

सचिन पायलट ने अपने अनशन के आयोजन पर किसी विधायक को आमंत्रित नहीं किया

—रेणु मिश्रल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। कल जयपुर में होने वाले अनशन से पूर्व सचिन पायलट का संदेश। राहुल गांधी दिल्ली में अडानी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और सचिन पायलट वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जयपुर में संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट के कल अपनी बड़ी ताकत दिखाने की उम्मीद है क्योंकि उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में जयपुर आएंगे। सचिन पायलट और उनके समर्थक पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को पूरा करने को लेकर संघर्षरत हैं। इन चुनावी वादों में वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ केस दर्ज करने की भी बात थी, लेकिन अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कभी नहीं किया। हालांकि, इस एक दिन के उपवास

पर, भीड़ के आने की संभावना से आशंकित गहलोत प्रयासरत हैं कि, अनशन को ज्यादा मीडिया अटेंशन ना मिले। यहां तक कि, एक प्रमुख न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित की कि, सचिन पायलट के खिलाफ कार्यवाही होगी। खबर के प्रसारण से अचम्भा है, क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान कार्यवाही किस मुंह से कर सकता है। जयराम रमेश व पवन खेड़ा ए.आई.सी.सी. के मीडिया सेल के कर्ताधर्ता जरूर जोर-शोर से यह प्रचारित कर रहे हैं कि, गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही की है। वे संजीवनी प्रकरण में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. का हवाला देते हैं। पर, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि, गहलोत सरकार ने यह तत्परता, वसुंधरा राजे के खिलाफ चर्चित भ्रष्टाचार के मामलों में क्यों नहीं दिखायी।

एक ऐसे नेता के खिलाफ कैसे कार्यवाही कर सकता है जो यह मांग कर रहा है कि एक भाजपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस का मीडिया विभाग जिसमें जयराम रमेश और पवन खेड़ा शामिल हैं, जो देरकर कर रहे हैं कि गजेन्द्र सिंह शेखावत के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि गहलोत की परम मित्र एवं प्रमुख समर्थक वसुंधरा राजे सिंधिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन गहलोत के प्रति जयराम और खेड़ा का प्रेम इस अंधत्व से भी आगे है।

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingolutions.com

एक और स्पायवेयर

"कोग्नाइट"

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्रालय ने पैगसस के विकल्प के रूप में

■ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, रक्षा मंत्रालय ने पैगसस के विकल्प के रूप में 986 करोड़ रु. में एक नया स्पायवेयर, कोग्नाइट खरीदा है, ताकि, विपक्षी दलों, एन.जी.ओ., मीडिया हाउस, जजों आदि की जासूसी की जा सके।

एक अन्य संचार उपकरण खरीदा है जिसका नाम है कोग्नाइट और इसके लिए (शेष पृष्ठ 5 पर)

देश भर में वकीलों की डिग्री की जांच होगी

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। एक बड़े घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के वकीलों की डिग्री के सत्यापन को हरी

■ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी तथा डिग्री के सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है।

झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वकीलों की डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट की (शेष पृष्ठ 5 पर)

शिव कुमार ने सिद्धारमैया का "चांस" खत्म करने के लिये खड़गे का नाम फेंका

कर्नाटक चुनाव में मु.मंत्री पद की दौड़ में मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिव कुमार व सिद्धारमैया का राजनीतिक द्वंद खुल कर सामने आया

—लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। सतही तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का केन्द्रीय एवं राज्य नेतृत्व कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्बिघ्न चुनाव प्रचार अभियान चला है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के दोनों दिग्गजों, पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार के बीच की प्रकट खुशामिजाजी में एक ही अंदरूनी तथ्य है, वह है उनकी परस्पर विध्वंसकारी शत्रुता और मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएँ और परस्पर विरोधी दावे।

ये दोनों ही जानते हैं कि उनके व्यक्तिगत भविष्य एक-दूसरे से और आपसी शांति से जुड़े हुए हैं। इनके बीच

■ कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं को इस घटनाक्रम से चिंता है कि, इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कांग्रेस की कसती डूब न जाये।

हाई कमान ने भी शांति स्थापित करवाई है, जिसे उम्मीद है कि कर्नाटक में पार्टी की जीत की अच्छी संभावनाएँ हैं। लेकिन मतदान का दिन आने से पहले इन दोनों के बीच नेतृत्व को लेकर संघर्ष तेज हो रहा है और ये दोनों ही एक-दूसरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित करने के प्रयास कर रहे हैं।

अब, सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनने का प्रयास शिव कुमार द्वारा खेले गए एक दलित कार्ड से खटाई में पड़

गया है। शिव कुमार ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की कि यदि पार्टी के शीर्ष नेता एवं ए.आई.सी.सी. अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हों तो उन्हें उनका पूरा समर्थन है। इस बयान से अब पार्टी में हलचल मच गई है। पार्टी के अंदरूनी लोग इसे सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के एक प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

पार्टी के भीतर के लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि जमीनी स्थिति कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इसे लेकर आशंकित भी हैं कि राज्य के दो शीर्ष नेताओं की प्रतिद्वंद्विता "सत्ता के बिल्कुल करीब किन्तु फिर भी दूर" वाली एक अन्य स्थिति को जन्म दे (शेष पृष्ठ 5 पर)

गहलोत ने रंधावा को भी मैनेज किया?

—रेणु मिश्रल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। कांग्रेस नेतृत्व अंधा हो गया है। नवीनतम घटनाक्रम में ऐसा लगता है कि

■ सूत्रों का कहना है कि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी टीम धन बल से एक के बाद एक ए.आई.सी.सी. महासचिव प्रभारी को मैनेज करती रही है, अविनाश पांडे ने तो जयपुर पहुंचने से पहले ही गहलोत का गुणगान शुरू कर दिया था, अब रंधावा भी यही कर रहे हैं।

राजस्थान के ए.आई.सी.सी. प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को अशोक (शेष पृष्ठ 5 पर)

पायलट के अनशन की "टाइमिंग" ने निरुत्तर किया ए.आई.सी.सी. को

—श्रीनन्द झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। राजस्थान में नेतृत्व की लड़ाई के मामले में, कांग्रेस हाई कमान द्वारा अशोक गहलोत गूट का पक्ष लेने के निर्णय के साथ, ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि जयपुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के एक दिन के अनशन के साथ ही राज्य की पार्टी इकाई के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्ञातव्य है कि पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर प्रकाश डालने के लिये एक दिन के उपवास की घोषणा कर दी है।

पायलट के इस कदम का समय अपने आप में महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जबकि राजस्थान के चुनाव भी करीब छः माह बाद होने हैं। और नये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी परिवार अभी तक भी पायलट को किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर समायोजित करने की इच्छा शक्ति नहीं दिला पाए हैं। पायलट के समर्थकों का

■ हाई कमान के पास कोई जवाब नहीं है कि, अभी तक उन तीन "दोषियों" के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, जिन्होंने बीस सितम्बर को हाई कमान के प्रतिनिधियों द्वारा आहूत विधायक दल की बैठक का बहिष्कार आयोजित कराया था।

■ इसी प्रकार मु.मंत्री गहलोत के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि, वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने खुद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, उनकी अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई।

कहना है कि पायलट को उनका देय अधिकार प्रदान करने तथा इसके लिये उन्हें राज्य पार्टी की इलैक्सन को-ऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक नियुक्त करने के लिये पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिये यह बिल्कुल सही समय है।

पायलट के खिन्न और दुखी होने के वाजिब कारण हैं। वे युवा हैं, सक्रिय एवं गतिशील हैं, प्रभावी वक्ता हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, वे पिछले साढ़े चार साल से हाशिये पर पड़े हुये हैं। कांग्रेस हाई कमान ने राज्य के उन दो मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की,

जिन्होंने विधायक दल की उस मीटिंग का बहिष्कार करने के लिये पार्टी विधायकों पर अपने प्रीव का इस्तेमाल किया था जो मीटिंग दो केन्द्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा बुलाई गई थी। ज्ञातव्य है कि इन दो पर्यवेक्षकों में से एक खड़गे भी थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के तत्कालीन कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रस्ताव की अवज्ञा कर देने के बाद भी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने हुये हैं, जबकि पायलट की भूमिका और कमतर हो गई है। (शेष पृष्ठ 5 पर)

पायलट के अनशन से गहलोत रक्षात्मक मुद्रा में आये

पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को अनशन स्थल पर न आने का आग्रह किया। वे गहलोत व वसुंधरा के खिलाफ इस लड़ाई को अपने स्तर पर ही लड़ना चाहते हैं

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की इस घोषणा कि वे वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार के शासनकाल में हुये भ्रष्टाचार के खिलाफ कल जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन के अनशन पर बैठेंगे, ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बैकफुट पर पहुँचा दिया है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिये हर तरह के दांव-पेज अपना रहे हैं।

गहलोत, जो एक चतुर राजनेता है, ऐसा दर्शा रहे हैं, मानो पार्टी और सरकार में सब कुछ सामान्य है, जबकि वे यह सुनिश्चित करने के लिये अपनी क्षमतानुसार हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि पायलट के उपवास-स्थल पर

ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो तथा मीडिया भी उधर ज्यादा ध्यान न दे। बताया जाता है कि सरकारी एजेंसियाँ राज्य में तथा खास तौर से राज्य की राजधानी में, न केवल पायलट बल्कि उनके सभी नजदीकी सहायकों-सहयोगियों तथा मित्रों को हर गतिविधि पर निगरानी रखने के काम में जी-जान से लगी हुई हैं।

जहाँ पायलट की गतिविधियों से गहलोत के खेम की घबराहट एवं अधीरता पैदा हो रही है, वहीं कांग्रेस के अन्दर भी विभिन्न प्रकार की आशंकाओं एवं डर का माहौल है क्योंकि वह इस साल के अन्त में राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है।

सचिन पायलट का कहना है कि वे गहलोत सरकार पर दबाव बनायेंगे

■ मजे की बात यह भी है कि, ए.आई.सी.सी. के मीडिया कक्ष के गहलोत समर्थक वक्तव्य के बावजूद पायलट के अनशन को दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का भूक समर्थन व सफाहना मिली है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे चुनाव अभियान का फोकस भी वहाँ की भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार है तथा पायलट के अनशन में उसकी प्रतिध्वनि है।

■ यह भी कहा जा रहा है कि, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कर्नाटक चुनाव, जो 10 मई को हैं, से पहले कोई राजनीतिक संकट नहीं चाहते पार्टी में, पर खड़गे ने भी भाजपा की पूर्व मु.मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग उठाना एक सराहनीय कृत्य बताया।

■ इस अनशन से पायलट ने एक दांव से, उन पर 2020 में भाजपा के साथ मिलकर बगावत करने के आरोप को धो दिया।

विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सचिन पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दे के समर्थन में कई विधायक उनके साथ होंगे। एक प्रमुख न्यूज चैनल ने यह स्टोरी चलाई थी कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लगता है कि, इस चैनल का दृष्टिकोण थोड़ा संकीर्ण है। पार्टी नेतृत्व

अनुप्रेष किया है कि वे उनके अनशन में शामिल न हों। सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री एक अकेले ऐसे राजनीतिक योद्धा के रूप में नज़र आना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री तथा भाजपा की वसुंधरा राजे दोनों के खिलाफ निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता का भ्रष्टाचार के

खिलाफ एक दिन का अनशन अपने प्रतिद्वंद्वी गहलोत के लिये नवीनतम चुनौती है लेकिन इस बार पायलट फूँक-फूँककर कदम रख रहे हैं। किन्तु भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती राजे सरकार (राजस्थान) पर उनके फोकस को कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता पसंद कर रहे हैं।

ऐसे समय, जब भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है तथा कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में उसने इसे एक मुद्दा बना लिया है, पायलट के इस कदम से जहाँ पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में भी सुनाई दे रही है।

कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन करते हुये जो बयान दिया है, ताकि ऐसा लगे कि हाई कमान एक ईमानदार निर्णायक की भूमिका अदा

करने जा रही है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नहीं चाहते, क्योंकि पार्टी कर्नाटक में करो या मरो की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है तथा वहाँ विधानसभा चुनाव 10 मई को ही होने हैं।

इसके साथ ही, खड़गे ने भाजपा सरकार के खिलाफ जाँच की, पायलट की माँग की सराहना की है। इस माँग के कारण, पायलट पर लगे वे पुराने आरोप धुल गये हैं कि उन्होंने 2020 में जो कुछ किया था, वह भाजपा के आदेश पर किया था।

हाई कमान इस तथ्य के प्रति सचेत है कि राजस्थान के चुनावों में आठ महीने ही रह गये हैं, इसलिये हो सकता (शेष पृष्ठ 5 पर)